

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह
सदस्य

निगरानी प्र० क्र० 2532-दो/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-03-14 पारित
अपर कलेक्टर, कटनी प्रकरण क्रमांक 02/बी-121/2012-13.

1- डा० विनोद कुमार गुप्ता आत्मज प्रेमनाथ गुप्ता
2- डा० श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नि डा० विनोदकुमार
3- डा० आशीष कुमार गुप्ता आत्मज विनोद कुमार
सभी निवासी ए-25, न्यू ए.सी.सी. कालोनी, कटनी
तह० व जिला कटनी म०प्र०
विरुद्ध
----- आवेदकगण

1- मध्यप्रदेश शासन
2- प्रशांत यादव आत्मज कैलोश नारायण
नि० सुभाष चौक कटनी
3- आर पी सिंह आत्मज ए पी सिंह
नि० हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी
4- मोहन शुक्ला (मृत) वारिसान-
अ- आदित्य शुक्ला पुत्र स्व. मोहन शुक्ला
ब- श्रीमती तारा शुक्ला पत्नि स्व. मोहन शुक्ला
नि० हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी
5- रमेश कुमार बजाज आत्मज नरसिंह दास बजाज
नि० हनुमान गंज वार्ड, कटनी
----- अनावेदकगण

श्री मोहम्मद जाहिद, अभिभाषक - आवेदक
श्री प्रमोद शुक्ला, अभिभाषक- अनावेदक क्र०-1 शासन
श्री जितेन्द्र शर्मा, अभिभाषक- अनावेदक क्र० 2 से 5
आदेश

(आज दिनांक ५ अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, कटनी के प्रकरण क्रमांक 02/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 25-03-14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।



में जारी किये गये हैं किन्तु पट्टेदारों का भूमि पर कब्जा नहीं है। नजूल तहसीलदार

ने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की और प्रशासनिक कारण बताई सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिये। प्रकरण के प्रचलित रहने में कारण नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 3-12-10 एवं 29-12-10 द्वारा राजस्व प्र0क0 90/अ-6-अ/92-93 पारित आदेश दिनांक 26-02-1993 को धारा 50 में लेकर अनावेदक क0 3 से 5 आर. के सिंह, मोहन शुक्ला एवं रमेशकुमार बजाज को सुनवायी हेतु तलबी के आदेश दिये और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 25-03-2014 में यह निष्कर्ष निकाला है कि क्रेतागण द्वारा ग्राम झिंझरी की भूमि खसरा नं0 301, 303 तथा 305 रकबा क्रमशः 0.28, 0.04 तथा 0.05 कुल रकबा 0.37 हे0 भूमि का पंजीयन कराये बिना ही अभिलेख सुधार कराया गया है जो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। अतः अपर कलेक्टर द्वारा राजस्व प्र0क0 90/अ-6-अ/92-93 में पारित आदेश दिनांक 26-02-1993 निरस्त कर उक्त भूमि पुनर्वास मद दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में उठाये गये मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक ने निगरानी में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि खसरा नं0 823/2 कुल रकबा 7.99 एकड़ बनवारीलाल पोद्दार के भूमिस्वामी हक की भूमि थी जिसमें से वर्ष 1973 से 1977 के



बीच में म0प्र0शासन ने रकबा 5.61 एकड़ भूमि पुनर्वास विभाग के माध्यम से अधिग्रहित की गयी तथा शेष रकबा 2.38 एकड़ (0.964 हे) बनवारीलाल पोद्दार के पास बचा जिसका नया खसरा नम्बर 302 है जिसे अनावेदक क्र0 3 लगायत 5 ने पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 28-04-1992 द्वारा क्रय किया गया। अनावेदक क्र0-3 लगायत 5 को ज्ञात होने पर क्रय किये गये रकबे का रकबा बन्दोवस्त के दौरान 0.964 हे0 के स्थान पर 0.53 हे0 दर्ज हो गया है, उन्होंने अभिलेख दुरुस्ती हेतु आवेदन धारा 115/116 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसे सहायक बन्दोवस्त अधिकारी ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 90/अ-6-अ/92-93 में पारित आदेश दिनांक 26-02-1993 द्वारा स्वीकार कर नवीन खसरा नं0 303 रकबा 0.03, खसरा नं0 304 रकबा 0.04, खसरा नं0 305 रकबा 0.10, खसरा नं0 301/3 रकबा 0.28 एवं खसरा नं0 302/1 रकबा 0.50 कुल रकबा 0.90 हे0 अनावेदक क्र0 3 लगायत 5 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। आवेदक निगरानीकर्ता द्वारा पुराने खसरा नं0 301/3 कुल रकबा 0.29 में से 0.07 हे. (वर्तमान में नया खसरा नं0 301/9) भूमि पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा अनावेदक क्र0 3 लगायत 5 से खरीदी है। इस भूमि के आवासीय/व्यवसायिक हेतु डायवर्सन कराया गया। और बाउन्डीवाल का निर्माण भी कराया गया है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि भूमि खसरा नं0 302/1, 303, 304, 305 तथा 301/3 कुल रकबा 0.90 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र नजूल अधिकारी, कटनी ने दिनांक 13-06-2001 को अनावेदक क्र0 3 लगायत 5 को जारी किया गया है। आवेदक की बाउन्डी खसरा नं0 301/9 रकबा 0.07 हे. पर मान्य किया। उनका तर्क है कि खसरा नं0 301/3 रकबा 1.40 आरे भूमि आबादी नजूल भूमि है। अपर कलेक्टर द्वारा सुनवायी का अवसर दिये बिना आबादी नजूल भूमि को आबादी पुनर्वास की भूमि में शामिल करने के आदेश देने में त्रुटि की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क्र0-1 शासन के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क्र0 3 लगायत 5 द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा कुल रकबा 0.53 हेक्टर भूमि खरीदी गयी थी, इस कारण बन्दोवस्त की त्रुटि के आधार पर अनावेदक क्र0 3 लगायत 5 को 0.90 हे. भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर द्वारा सहायक

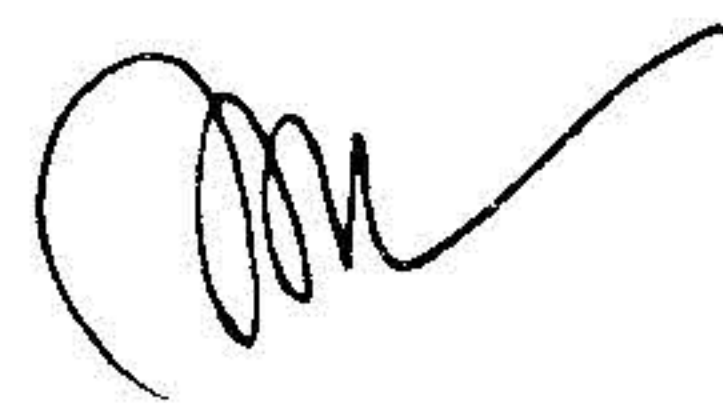


बन्दोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 26-02-1993 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि आबादी पुनर्वास में शामिल करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक क0 2 के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क0 3 लगायत 5 के भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज होने से अनावेदक द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा खरीदी है और वह सद्भाविक क्रेता है। उनका यह भी तर्क है कि 1993 के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 25-03-2014 द्वारा लगभग 21 वर्ष पश्चात निरस्त किया है जो समयावधि बाह्य है। स्वमेव निगरानी की कार्यवाही इतने अधिक विलम्ब से नहीं की जा सकती।

6/ अनावेदक क0 3 से 5 के अभिभाषक का यह तर्क है कि बनवारीलाल पोद्दार के स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 2.38 एकड़ (0.964 हे) थी जिसे अनावेदक क0 3 लगायत 5 ने पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया गया है। अनावेदक क0-3 लगायत 5 को ज्ञात होने पर की क्रय किये गये रकबे का रकबा बन्दोवस्त के दौरान 0.964 हे0 के स्थान पर 0.53 हे0 दर्ज हो गया है, उन्होंने अभिलेख दुरुस्ती हेतु आवेदन धारा 115/116 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसे सहायक बन्दोवस्त अधिकारी ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 90/अ-6-अ/92-93 में पारित आदेश दिनांक 26-02-1993 द्वारा जॉच उपरान्त स्वीकार किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अपर कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को शासकीय मानते हुए पुनर्वास मद में दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

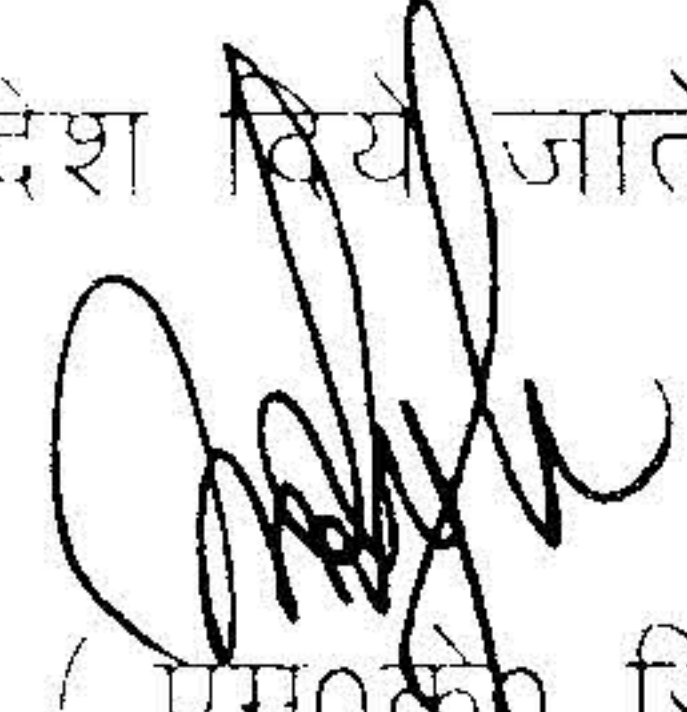
7/ विचारण न्यायालय के अभिलेख में पृष्ठ 251 पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षकों के प्रतिवेदन व स्थल पंचनामों से स्पष्ट है कि नक्शे में खसरा नं0 302/2 रकबा 0.03 हे. आबादी पुनर्वास अंकित है और शेष रकबा भूमिस्वामी स्वत्व का है। अनावेदक क0 3 से 5 द्वारा नजूल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहे जाने पर नजूल अधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि चकबन्दी के पश्चात ख0नं0 823/2 रकबा 7.99 एकड़ बनवारीलाल पोद्दार के नाम पर



भूमिस्वामी हक में अंकित थी जिसमें से पुनर्वास विभाग द्वारा 823/2 का भाग 5.61 एकड़ रकबा अधिग्रहित किया गया और शेष रकबा 2.38 एकड़ भूमिस्वामी स्वत्व में बचा। अनावेदक क्र0 3 से 5 द्वारा बनबारीलाल पोद्दार से भूमि खरीदी गयी है। सहायक बन्दोवस्त अधिकारी ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 90/अ-6-अ/92-93 में पारित आदेश दिनांक 26-02-1993 द्वारा विधिवत जाँच उपरान्त बन्दोवस्त के दौरान 0.964 हे. के स्थान पर 0.53 हे. दर्ज किये जाने से अभिलेख सुधार के आदेश पारित किये गये हैं। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में उक्त तथ्य त्रुटिपूर्ण होने संबंधी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। इससे स्पष्ट है कि 0.37 हे. भूमि शासकीय ना होकर भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। अपर कलेक्टर ने अनावेदक क्र0-3 से 5 द्वारा भूमिस्वामी बनबारीलाल पोद्दार से 0.964 हे. के स्थान पर 0.53 हे. भूमि पंजीयत विक्रयपत्र के आधार पर क्रय करने से सहायक बन्दोवस्त अधिकारी का राजस्व प्रकरण क्रमांक 90/अ-6-अ/92-93 में पारित आदेश दिनांक 26-02-1993 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 0.37 हे. पुनर्वास मद में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। सहायक बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन बिन्दु यह था कि क्या बन्दोवस्त के दौरान रकबे में त्रुटि हुई है ? बन्दोवस्त के दौरान जाँच उपरान्त रकबे में त्रुटि पाये जाने से सहायक बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26-02-1993 पारित किया गया। बन्दोवस्त के दौरान रकबे में त्रुटि नहीं हुई, यह निष्कर्ष निकाले बिना अपर कलेक्टर द्वारा सहायक बन्दोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 26-02-93 लगभग 21 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में धारा 50 के अन्तर्गत निरस्त करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा न0 301/3 में से 0.07 हे. जिसका नवीन ख न0 301/9 है। को पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा खरीदी गयी है तथा इस भूमि के आवासीय/व्यवसायक उपयोग हेतु डायवर्सन कराने के पश्चात बाउन्डीवाल का निर्माण किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवायी हेतु कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया, जबकि आवेदक हितग्राही पक्षकार था। ऐसी दशा में आवेदक को सुनवायी का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।



8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 25-03-2014 निरस्त किया जाता है एवं भूमि स्वामी आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते हैं ।



(एम0के0 सिंह)

सदस्य,

राजस्व मण्डल, म0प्र0

ग्वालियर,